

V. K. Construction Works (P) Ltd. v. M/s. Food Corporation
of India and another. (D. S. Tewatia, J.)

डी. एस. तेवतिया जे.के समक्ष

वी.के. कंस्ट्रक्शन वर्क्स (पी) लिमिटेड,-अपीलकर्ता।

बनाम

एम/एस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

और दूसरा,—प्रतिवादी.

1983 के आदेश क्रमांक 247 से प्रथम अपील।

और 1983 की क्रॉस-आपत्ति संख्या 48-सीआईआई।

30 मई 1986.

मध्यस्थता अधिनियम (1940 का X) - धारा 8 और 20(4) - मध्यस्थता समझौता विशेष रूप से एक निदिष्ट प्राधिकारी को मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है - ऐसा करने में विफल रहने पर नियुक्ति करने का हकदार प्राधिकरण - जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है - क्या यह किसी पक्ष को मध्यस्थ की तलाश करने का अधिकार नहीं देता है मध्यस्थता का संदर्भ.

अभिनिर्धारित, कि मूल प्रावधान जो न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार प्रदान करता है वह मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 है, और धारा 20 के प्रावधान इसे लागू करने के लिए सही मशीनरी प्रदान करते हैं। अधिनियम की धारा 8 के तहत न्यायालय एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है (1) या तो जब समझौते में दोनों पक्षों की सहमति से एक मध्यस्थ का संदर्भ प्रदान किया गया हो और पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति में सहमत नहीं थे, और (2) यदि नियुक्त मध्यस्थ कार्य करने की उपेक्षा करता है या इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या मर जाता है तो मध्यस्थता समझौते में यह नहीं दिखाया गया है कि इसका इरादा था कि रिक्ति की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए और पार्टियों या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो। हालाँकि, जहाँ उपरोक्त दो स्थितियाँ उपलब्ध नहीं हैं और यदि किसी कारण से मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया है या मध्यस्थ नियुक्त किया गया है तो वह कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो एक पक्ष मध्यस्थता का संदर्भ लेने का हकदार है।

(पैरा 5 और 6)

वेद प्रकाश मितल बनाम भारत संघ एवं अन्य ए.आई.आर. 1984 दिल्ली 325

(से असहमत)

श्रीमान के आदेश से प्रथम अपील। बाबू राम गुप्ता, एचसीएस सब जज प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ ने 5 फरवरी, 1983 को याचिका खारिज कर दी और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया।

प्रति-आपत्ति संख्या 1983 का 48-एस-II.

प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से प्रार्थना करते हुए कि उत्तरदाताओं की प्रतिवाद को स्वीकार किया जा सकता है और मुद्दे संख्या 2 से 5 तक उत्तरदाताओं के पक्ष में और याचिकाकर्ता आवेदकों के खिलाफ निर्णय लिया जा सकता है।

अपीलकर्ता की ओर से आर. एस. मोंगिया, अधिवक्ता सतिंदर बंसल के साथ
गोपी चना, अधिवक्ता -प्रतिवादियों की ओर से

निर्णय

डी. एस. तेवतिया, जे.

(1) वादी के कहने पर यह अपील ट्रायल कोर्ट के 5 फरवरी 1983 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें वादी की 5 फरवरी 1982 की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के तहत उनके बीच समझौते को दाखिल करने की मांग की गई थी। 1940 के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, और उक्त अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में पार्टियों के बीच विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा गया है।

(2) ट्रायल कोर्ट ने वादी के आवेदन को अनुचित मानते हुए खारिज कर दिया ।

इस आधार पर कि अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान थे।

(3) बार में उठाए गए 11 प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, इस स्तर पर अधिनियम की धारा 8 और धारा 20 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा:

“8. (1) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में-

(ए) जहां एक मध्यस्थता समझौते में यह प्रावधान है कि संदर्भ एक या एक से अधिक मध्यस्थों को होगा, जिन्हें पार्टियों की सहमति से नियुक्त किया जाएगा, और मतभेद उत्पन्न होने के बाद सभी पार्टियां नियुक्ति या नियुक्तियों में सहमत नहीं होती हैं; या

(बी) यदि कोई नियुक्त मध्यस्थ या अंपायर उपेक्षा करता है या कार्य करने से इनकार करता है, या कार्य करने में असमर्थ है, या मर जाता है, और मध्यस्थता समझौते से पता नहीं चलता है कि इसका उद्देश्य यह था कि रिक्ति की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए और पार्टियों या मध्यस्थों को जैसा भी मामला हो, रिक्ति की आपूर्ति न करें; या

(सी) जहां पार्टियों या मध्यस्थों को एक अंपायर नियुक्त करने की आवश्यकता होती है और उसे नियुक्त नहीं करते हैं;

कोई भी पक्ष अन्य पक्षों या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, नियुक्ति या नियुक्तियों की आपूर्ति में सहमति देने के लिए लिखित नोटिस दे सकता है।

(2) यदि उक्त नोटिस की तामील के बाद पंद्रह स्पष्ट दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं की जाती है, तो न्यायालय, नोटिस देने वाले पक्ष के आवेदन पर और अन्य पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। मध्यस्थ या

V. K. Construction Works (P) Ltd. v. M/s. Food Corporation
of India and another. (D. S. Tewatia, J.)

अंपायर के पास संदर्भ में कार्य करने और निर्णय देने की समान शक्ति होगी, जैसे कि उन्हें सभी पक्षों की सहमति से नियुक्त किया गया हो।

* * * * *

20. (1) जहां किसी व्यक्ति ने समझौते के विषय-वस्तु या उसके किसी भाग के संबंध में किसी मुकदमे की स्थापना से पहले मध्यस्थता समझौता किया है, और जहां कोई अंतर उत्पन्न हुआ है कि समझौता किस पर लागू होता है, इसके बजाय वे या उनमें से कोई भी अध्याय II के तहत कार्यवाही, समझौते से संबंधित मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय पर लागू हो सकती है, ताकि समझौता न्यायालय में दायर किया जा सके।

(2) आवेदन लिखित रूप में होगा और "हितबद्ध होने का दावा करने वाले एक या अधिक पक्षों के बीच वादी या वादी के रूप में और शेष को प्रतिवादी या प्रतिवादी के रूप में, मुकदमे के रूप में क्रमांकित और पंजीकृत किया जाएगा। अन्यथा, आवेदक या वादी और प्रतिवादी के रूप में अन्य पक्षों के बीच आवेदन सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(3) इस तरह के आवेदन किए जाने पर, न्यायालय आवेदकों के अलावा समझौते के सभी पक्षों को नोटिस देने का निर्देश देगा, जिससे उन्हें नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की आवश्यकता होगी कि समझौता क्यों दाखिल नहीं किया जाना चाहिए।

(4) जहां कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया, अदालत समझौते को दायर करने का आदेश देगी और पार्टियों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को संदर्भ का आदेश देगी, चाहे समझौते में हो या अन्यथा, या जहां पार्टियां एक मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकती हैं।

(5) इसके बाद मध्यस्थता इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी और उनके द्वारा शासित होगी, जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है।

अपीलकर्ता के वकील श्री आर.एस. मोंगिया ने वेद प्रकाश मितल बनाम भारत संघ और अन्य (1) में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के आधार पर कहा कि न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं थी और न्यायालय समझौते को दाखिल करने का आदेश देने और मध्यस्थ को विवाद का संदर्भ देने के लिए सक्षम नहीं था। विद्वान वकील ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि मध्यस्थता खंड, जिसे पूर्ण पीठ द्वारा समझा गया, उसी के समान था जिसे हाथ में मामले में समझा जाना आवश्यक है और फिर निष्कर्ष निकाला कि

(1)A.I.R. 1984 Delhi 325.

पूर्ण पीठ के फैसले ने पूरी तरह से वर्तमान मामले को कवर किया।

(4) वर्तमान मामले में समझौते में मध्यस्थता खंड, जो प्रतिवादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील के अनुसार, मामले में मध्यस्थता को बंद कर देता है, इस प्रकार चलता है: "25. सिवाय इसके कि जहां अन्यथा अनुबंध में प्रावधान किया गया है, यहां पहले

उल्लिखित विशिष्टताओं, डिजाइनों, रेखाचित्रों और निर्देशों के अर्थ और काम में उपयोग की जाने वाली कारीगरी या सामग्री की गुणवत्ता या किसी अन्य प्रश्न से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद, दावा, सही मामला या चीज़, जो भी हो, किसी भी तरह से अनुबंध, डिजाइन, चित्र, विनिर्देश, अनुमान, निर्देश, आदेश या इन शर्तों से उत्पन्न या उससे संबंधित या अन्यथा कार्यों या निष्पादन से संबंधित हो या उसे निष्पादित करने में विफलता, चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या कार्य के बाद या उसके पूरा होने या त्यागने के बाद उत्पन्न हो, प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित की जाएगी। विवाद के समय भारतीय खाद्य निगम, या यदि कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, तो ऐसी नियुक्ति के समय उक्त निगम का प्रशासनिक प्रमुख। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त किया गया मध्यस्थ एक निगम कर्मचारी है, कि उसे अनुबंध से संबंधित मामलों से निपटना होगा, और निगम कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने व्यक्त किया था विवाद या मतभेद वाले सभी या किसी भी मामले पर विचार। जिस मध्यस्थ को मामला मूल रूप से भेजा गया है, उसका स्थानांतरण हो रहा है या उसका कार्यालय खाली हो रहा है या उसकी मृत्यु हो रही है या वह किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, ऐसे स्थानांतरण के समय उपरोक्त प्रबंध निदेशक या प्रशासनिक प्रमुख, कार्यालय की छुट्टी या असमर्थता अधिनियम, अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति उपरोक्त संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा, जिस पर यह उसके पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ा गया था। इस अनुबंध की एक शर्त यह भी है कि ऐसे प्रबंध निदेशक या प्रशासनिक प्रमुख द्वारा किसी अन्य संस्करण की नियुक्ति नहीं की जाएगी

उपरोक्तानुसार निगम को मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए और यदि किसी कारण से यह संभव नहीं है, तो मामले को मध्यस्थता के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाना चाहिए।

किशन चंद बनाम भारत संघ और अन्य (2) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को पूर्ण पीठ ने पलट दिया था, जिसे निम्नानुसार माना गया था:

"हमें यह स्पष्ट लगता है कि वर्तमान मामले में धारा 8(1)(ए) का सहारा नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अनिवार्य शर्त यह है कि मध्यस्थता समझौता ऐसा होना चाहिए जो यह प्रदान करता हो कि संदर्भ एक या अधिक के लिए पार्टियों की सहमति से नियुक्त किया जाएगा।" यहां मध्यस्थता खंड यह 'प्रदान' नहीं करता है। इसके विपरीत, यह एक मध्यस्थ को नामित करने की शक्ति विशेष रूप से मुख्य अभियंता और, एक स्थिति में, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक प्रमुख में निहित करता है। उपधारा में 'प्रदान करता है' का उपयोग 'स्पष्ट रूप से निर्धारित' करने के लिए किया जाता है। जब एक मध्यस्थता यह निर्धारित करता है कि उप-धारा क्या कहती है, तो उप-धारा लागू होती है अन्यथा नहीं। अन्य विशिष्ट प्रकार के मध्यस्थता समझौते का निपटारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 और 10 में किया गया है। वे यह भी बताते हैं कि मध्यस्थता समझौते को लागू करने के लिए उन्हें क्या 'प्रदान' करना चाहिए। इनमें से कोई भी 8, 9 या 10 अनुभाग नहीं, इसे अर्थ में सामान्य अनुप्रयोग के हैं कि उन्हें मध्यस्थता समझौते के हर ज्ञात या बोधगम्य रूप पर लागू किया जा सकता है, भले ही यह 'क्या प्रदान करता है'।

धारा 8(1)(ए) को वर्तमान मामले में मौजूद समझौते पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि इसके द्वारा परिकल्पित नोटिस दिया जाना असंभव है। याचिकाकर्ता मध्यस्थ की नियुक्ति में भारत संघ (समझौते के 'अन्य पक्ष') से सहमति की उचित मांग नहीं कर सकता, क्योंकि समझौता 'प्रदान' नहीं करता है। इसके बजाय, याचिकाकर्ता ने जो नोटिस भेजा है उसमें मुख्य अभियंता से एक मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की है। ऐसा नोटिस धारा 8(1)(ए) की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह 'अन्य पार्टी' को संबोधित नहीं है जो कि मुख्य अभियंता निश्चित रूप से नहीं है; और भी

(2) I.L.R. (1974) II, Delhi 637

V. it. Construction Works (P) Ltd. v M/s. Food Corporation
of India and another. (D. S. Tewatia, J.)

ऐसा नहीं होता है और समझौते के आलोक में, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति नहीं मांगी जा सकती है। इन कारणों से, जिन्हें हमने संक्षेप में बताया है, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं होगी कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8(1)(ए) इस मामले पर लागू नहीं होती है, और न्यायालय में कोई शक्ति नहीं है। ऐसा उपधारा के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए हुआ है।"

चावला, जे. जिन्होंने डिवीजन "बेंच के लिए राय दी, ने विपरीत दृष्टिकोण पेश करने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों पर ध्यान दिया और उन्हें अलग किया। अधिनियम की धारा 20(4) के प्रावधानों से निपटते समय, विद्वान न्यायाधीश ने देखा कि उक्त प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की दूसरी अनुसूची के पैराग्राफ 17 पर आधारित था, जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ जोड़े गए खंडों पर नोटिस से स्पष्ट हुआ जो मध्यस्थता अधिनियम बन गया। उपरोक्त अनुच्छेद 17 का उप-अनुच्छेद 4 निम्नलिखित शब्दों में था:

"जहां कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, अदालत समझौते को दायर करने का आदेश देगी, और समझौते के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ को संदर्भ का आदेश देगी, या, यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और पक्ष सहमत नहीं हो सकते, न्यायालय एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।"

विद्वान न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के प्रावधान के साथ उक्त उप-पैराग्राफ की तुलना निम्नलिखित शब्दों में करने का प्रयास किया:

"धारा 20(4) के साथ इस उप-पैराग्राफ की तुलना से पता चलता है कि 'समझौते में पार्टियों द्वारा नियुक्त'... शब्दों को समझौते के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए गए शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, और शब्द 'यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो' शब्दों के स्थान पर 'अन्यथा' प्रतिस्थापित कर दिया गया है। वर्तमान वाक्यांशों को पहले के समकक्षों के संदर्भ में प्रस्तुत करने से पता चलता है कि 'समझौते में पार्टियों द्वारा नियुक्त समझौते के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त का प्रतीक है'। और, 'अन्यथा' कब है

'ऐसा कोई प्रावधान नहीं है' - जो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम मेसर्स के दृष्टिकोण से मेल खाता है। घरेलू इंजीनियरिंग स्थापना, (3). 'अन्यथा' शब्द का उद्देश्य और प्रभाव समझौते के अलावा पार्टियों द्वारा 'अन्यथा' किए गए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी देने के लिए न्यायालय में व्यक्त शक्ति निहित करना है। पहले उप-पैराग्राफ में ऐसी स्पष्ट शक्ति की आवश्यकता थी, हालांकि शायद इसका वैध अनुमान लगाया जा सकता था।

चावला, जे. ने मध्यस्थता समझौते के रेखांकित भाग की व्याख्या करते हुए, जिस पर प्रतिवादी-प्रतिवादी का मामला निर्भर था, निम्नलिखित कहा:

"यह मानते हुए कि धारा 8(1)(बी) की आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरी हो गई हैं,

Construction Works (P) Ltd. v. M/s. Food Corporation
of India and another. (D. S. Tewatia, J.)

जिसमें दूसरे पक्ष को नोटिस देना भी शामिल है, हालांकि ये ऐसे मामले हैं जिन पर हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं, फिर भी, हमें ऐसा लगता है, न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति में एक बड़ी बाधा है। यह याद किया जाएगा कि मध्यस्थता खंड स्पष्ट रूप से कहता है:

'इस अनुबंध की एक शर्त यह भी है कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के ऐसे मुख्य अभियंता या प्रशासनिक प्रमुख द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, और यदि, किसी भी कारण से, यह संभव नहीं है, मामले को मध्यस्थता के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाना चाहिए।'

जाहिर है, इस शर्त का उद्देश्य मध्यस्थता अधिनियम के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की न्यायालय की शक्ति को नकारना था। संभवतः, किसी भी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के पास समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों को निर्धारित करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति न हो सकती है या प्राप्त हो सकती है। यह शर्त इतनी सटीक है कि यदि, किसी भी कारण से, यह संभव है कि एक मध्यस्थ को मुख्य अभियंता या सी.पी.डब्ल्यू.डी. के प्रशासनिक प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाए, तो मध्यस्थता समझौता स्वयं नष्ट हो जाता है।

(3) A.I.R. 1970 All. 31

'रसेल ऑन द लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन', 18वें संस्करण, पृष्ठ 1 के निम्नलिखित पैराग्राफ का उल्लेख करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने देखा कि ऐसी शर्त अमान्य नहीं थी:

“मध्यस्थता के पक्षकार बड़े पैमाने पर स्वयं पालन की जाने वाली प्रक्रिया और मध्यस्थ के पास होने वाली शक्तियों के साथ-साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण के संविधान का निर्धारण कर सकते हैं। अधिनियम इन सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक कोड निर्धारित करता है, लेकिन इसके कई प्रावधानों को पार्टियों के बीच समझौते से बाहर रखा जा सकता है।

चावला, जे. का विचार था कि उपरोक्त तथ्य दो अंग्रेजी मामलों से सामने आया है और उन्होंने कहा:

“यह इन रे एन आर्बिट्रेशन बिटवीन विलियम्स एंड स्टेपनी, (4) एंड इन रे एन आर्बिट्रेशन बिटवीन विल्सन एंड संस, एंड द ईस्टर कंट्रीज नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, (5) दो अंग्रेजी मामलों से पता चलता है। इन मामलों के उत्तरार्ध में सवाल यह था कि क्या न्यायालय अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम 1899 की धारा 5(बी) के तहत मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है, जो भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 8(1)(बी) के लगभग समान था। इस प्रश्न से निपटते हुए, श्री न्यायमूर्ति ए.एल. स्मिथ ने कहा:

अधिनियम कुछ प्रावधानों को प्रस्तुत करने के लिए लागू होता है, जब तक कि इसके विपरीत प्रावधान न किया गया हो। वर्तमान मामले में इसके विपरीत प्रावधान किया गया है।

यहां भी यही स्थिति है। इसलिए, हम मानते हैं कि न्यायालय के पास धारा 8(1)(बी) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि उस शक्ति को मध्यस्थता खंड द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

वेद प्रकाश के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ ने अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और धारा 8(1)(बी) के प्रावधानों की अनुपयुक्तता के संबंध में डिवीजन बेंच के विचार का पूरी तरह से समर्थन किया।

V. *it. Construction Works (P) Ltd. v M/s. Food Corporation of India and another. (D. S. Tewatia, J.)*

- (4) (1891) 2 Q.B.D. 257.
- (5) (1891) 1 Q.B.D. 81



पहले उल्लिखित मध्यस्थता खंड में शर्तों के सामने, अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के निर्माण और प्रयोज्यता के संबंध में एक विपरीत दृष्टिकोण की जोरदार वकालत की गई। पूर्ण पीठ ने इस संबंध में अपना विचार निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया:

“किशन चंद के मामले (सुप्रा) में, विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि धारा 20(4) के तहत न्यायालय ऐसी स्थिति से निपटने में असमर्थ होगा जिसमें नामित व्यक्ति विफल हो या नियुक्ति से इनकार कर दिया। बड़े सम्मान के साथ, हम इस निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं।

पूर्ण पीठ ने तब इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के तहत न्यायालय मुख्य अभियंता को निर्देश दे सकता है, जिसे मध्यस्थता खंड के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त करना था और उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि जब न्यायालय को मुख्य अभियंता को मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश देना था, तो मुख्य अभियंता न्यायालय के आदेश का पालन करेगा, और यदि न्यायालय के निर्देश के बावजूद, उसने नियुक्ति करने से इनकार कर दिया, तो न्यायालय ऐसा नहीं करेगा। शक्तिहीन, उस स्थिति में यह स्वयं नियुक्ति कर सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह एक ऐसा मामला होगा जहां 'पक्षकार मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकते' और उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए, पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने मांग की यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सान्याल, (6) में निम्नलिखित टिप्पणियों से समर्थन:

"वर्तमान मामले में, चूंकि पार्टियों द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया है और चूंकि पार्टियां एक मध्यस्थ पर सहमत नहीं हैं, इसलिए न्यायालय एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा करने में यह वांछनीय है कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने की व्यवहार्यता पर न्यायालय को विचार करना चाहिए। इस मामले में प्रतिवादी ने अपनी याचिका में समझौते की शर्तों के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की है। हमारे समक्ष दोनों पक्षों ने इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रपति को समझौते की धारा 29 के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहा जाना चाहिए। हमें लगता है कि इस सझाव पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है और तदनुसार हम राष्ट्रपति से आज से दो महीने के भीतर खंड 29 के तहत विचार के अनुसार एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहते हैं।

(6)A.I.R. 1979 S.C. 1457.

इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ तुरंत अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और संदर्भ का यथाशीघ्र निपटान करेगा। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। राष्ट्रपति आज से दो महीने के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, ऐसा न करने पर श्री तपश बनर्जी, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे जब भारत संघ के वकील ने पूर्ण पीठ के ध्यान में लाया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले में - प्रफुल्ल कुमार सान्याल का मामला (सुप्रा), मध्यस्थता खंड में ऐसी कोई शर्त नहीं थी जैसा कि किशन चंद के मामले में था (सुप्रा) और, इसलिए, किशन चंद के मामले में (सुप्रा) कानून सही ढंग से निर्धारित किया गया था, विद्वान न्यायाधीश उस सबमिशन से असहमत थे और निम्नानुसार कहा गया था:

“मुख्य अभियंता मध्यस्थ नहीं है। वह पार्टियों का चुना हुआ नियुक्तकर्ता है। यह सच है कि वह विवाद के एक पक्ष का कर्मचारी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी का पक्ष ले सकता है। उसे धारा के तहत अपना कर्तव्य निभाना होगा। पार्टियों ने उन पर और उनकी ईमानदारी पर भरोसा जताया है। सरकार पर वह कोई एहसान नहीं जताएंगे। वह मालिक के प्रति न तो वफादार हो सकता है और न ही बेवफा। वह पार्टियों का न तो दोस्त हो सकता है और न ही दुश्मन। यदि मुख्य अभियंता मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं करता है तो उसे अपने इनकार को उचित ठहराना होगा और कारणों सहित इसका समर्थन करना होगा। यदि इनकार मनमाना है तो न्यायालय मुख्य अभियंता को सुधारेगा और उसे बताएगा कि उसकी इयूटी कहाँ है। उसे मध्यस्थ नियुक्त करने का कर्तव्य दिया गया है न कि खंड को नष्ट करने का। यह कहना खंड की गलत व्याख्या है कि यदि मुख्य अभियंता मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करता है तो न्यायालय शक्तिहीन है। डिवीजन बैंच के न्यायाधीशों का ऐसा दृष्टिकोण इस आधार पर धारा 20(4) के प्रावधानों की प्रभावशीलता को कम करता है कि यह उस मामले का प्रावधान नहीं करता है जो डिवीजन बैंच के समक्ष और इस पूर्ण बैंच में हमारे सामने आया था। विधायिका ने अनुमान लगाया कि ऐसा मामला उत्पन्न हो सकता है और इसलिए, धारा 20 में प्रावधान है कि न्यायालय इस पाठ्यक्रम का पालन करेगा। सबसे पहले, न्यायालय नामित व्यक्ति से मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहेगा। दूसरे, यदि वह नियुक्ति नहीं करता है तो न्यायालय नियुक्ति करेगा

जहां पार्टियां मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो पाती हैं, वहां न्यायालय तुरंत आता है और मध्यस्थ की नियुक्ति करता है। प्रफुल्ल कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही तरीका अपनाया (सुप्रा)। और इस मामले में हम इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं।

जैसा कि हमने ऊपर कहा है, मुख्य अभियंता निश्चित रूप से एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा जब न्यायालय उसे ऐसा करने का निर्देश देगा, भारत संघ की आपत्तियों को सुनने के बाद, जो किसी न किसी आधार पर नियुक्ति का विरोध करते हैं। मुख्य अभियंता को अपने इनकार का कारण बताना होगा। यदि मुख्य अभियंता का कारण काफी संतोषजनक है तो न्यायालय उससे सहमत हो सकता है और मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार कर सकता है और उस स्थिति में मध्यस्थता समझौते को दाखिल करने से इनकार कर सकता है। लेकिन कारण तो उसे बताना ही होगा। कार्य करने का कोई अच्छा कारण होना चाहिए। और कार्रवाई न करने का कोई अच्छा कारण होना चाहिए। मुख्य अभियंता को विवेकपूर्ण और ठोस दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पार्टी को यह जानने का अधिकार है कि वह मध्यस्थ की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके बाद न्यायालय उसके तर्क पर फैसला सुनाएगा। यदि कारण खराब है तो न्यायालय उसे मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश देगा। यह उतना ही सरल है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह न्यायालय का पालन करेंगे और धारा के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

जिस खंड को डिवीजन बेंच ने एक 'पूर्ण' शर्त माना था, उसमें दो महत्वपूर्ण शब्दों 'कारण' और 'संभव' का उपयोग किया गया है। ये कड़े शब्द हैं। मुख्य अभियंता की कार्रवाई तर्क से तय होनी चाहिए। मनमौजीपन के विपरीत तर्क का प्रयोग किया जाता है। 'संभव' शब्द का अर्थ है कि यह व्यावहारिक के दायरे में है। यदि यह संभावना की सीमा के भीतर है तो मुख्य अभियंता को अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। जहां मुख्य अभियंता का कार्यालय समाप्त कर दिया गया है और विभाग का कोई प्रशासनिक प्रमुख भी नहीं है, वहां मध्यस्थ नियुक्त करना असंभव हो सकता है। उस मामले में, यह तर्क दिया जा सकता है कि मामले को मध्यस्थता के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाना चाहिए। हम उन मामलों की कल्पना कर सकते हैं जहां मध्यस्थ का नामांकित व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है। लेकिन जब तक मुख्य अभियंता का कार्यालय मौजूद है, हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति में एक 'असाध्य बाधा' हो सकती है, जैसा कि डिवीजन बेंच ने सोचा था।

किशन चंद का मामला, धारा 20(4) से पता चलता है कि मुख्य अभियंता द्वारा इनकार पर काबू पाया जा सकता है। इस खंड में कुछ भी नया नहीं है, जो कहता है कि मुख्य अभियंता द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारण से, यह संभव नहीं है तो मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाएगा।

धारा दर्शाती है कि मुख्य अभियंता न्यायालय के प्रति जवाबदेह है। वह यह नहीं कह सकते कि वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, जैसा कि भारत संघ की ओर से हमारे सामने तर्क दिया गया था। वह धारा 20(4) के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। वह कानून से ऊपर नहीं है। न ही वह अपने लिए कोई कानून है। जिस अनुबंध में मध्यस्थता खंड शामिल है वह एक व्यावसायिक दस्तावेज़ है। हमें इसे व्यावसायिक प्रभावकारिता देनी चाहिए ताकि पार्टियों के इरादे को प्रभावी बनाया जा सके। हम ठेकेदार के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे यदि हम उसे बताएं कि मुख्य अभियंता ने धारा को नष्ट कर दिया है और हम उसकी शिकायत का निवारण करने में असमर्थ हैं।

मान लीजिए कि मुख्य अभियंता मध्यस्थ नियुक्त करने से इंकार कर देता है या उपेक्षा करता है, तो हम यहां से कहा जाएंगे? क्या न्यायाधीश हाथ जोड़कर कह सकता है, 'मेरे पास कोई शक्ति नहीं है' उस स्थिति में मध्यस्थता समझौता स्वयं नष्ट हो जाता है। लेकिन इसे रोकना खतरनाक है। हमारी राय में, धारा 20(4) निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आने वाले मामले को समझती है। धारा 4 अधिनियमित करती है कि नामित व्यक्ति मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। लेकिन धारा 20(4) के तहत शेष क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायालय मध्यस्थता समझौते को प्रभावी बनाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने के पक्ष में झुकेगा। हमें किशन चंद (सुप्रा) मामले में डिवीजन बेंच द्वारा प्रतिपादित हैंड-ऑफ सिद्धांत को न्यायिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उन्होंने धारा 20(4) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया। इस प्रकार, न्यायालय की शक्ति समाप्त हो गई। परिणाम यह हुआ कि धारा नष्ट हो गई और न्यायालय की शक्ति नष्ट हो गई। हम खंड के अर्थ पर ऐसे निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते।

किशन चंद में डिवीजन बेंच का प्रमुख विषय यह है कि मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति मुख्य में अभियंता। उन्होंने सोचा, न्यायालय में कोई शक्ति नहीं है। उनके तर्क के अनुसार नियुक्ति करना या अस्वीकार करना मुख्य अभियंता का विशेषाधिकार है और कोई भी उनके निर्णय पर सवाल

नहीं उठा सकता। जैसे ही मुख्य अभियंता इनकार करते हैं, धारा समाप्त हो जाती है। उनका मानना है कि यदि नियुक्तिकर्ता ने नियुक्ति से इनकार कर दिया तो मध्यस्थता करना असंभव होगा। उनके तर्क की यही पंक्ति है। हमारी सम्मानजनक राय में यह एक भ्रामक तर्क है। वे मुख्य अभियंता को जो पूर्ण शक्ति देते हैं, वह कानून के लिए अज्ञात हैं, चाहे क्षेत्र कोई भी हो - अनुबंध या प्रशासनिक कानून। मुख्य अभियंता को एक मंत्रिस्तरीय कार्य करना होता है। वह एक तीसरा पक्ष है। मुकदमे के पक्षकार के साथ उसकी पहचान करना एक भ्रम है। यह और बात है कि विवाद उनके विभाग से संबंधित हैं और वे सरकार के अपने आदमी हैं। लेकिन उनकी भूमिका गौण है। उसे प्रधानता का स्थान नहीं दिया जा सकता। उसे इस खंड को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। समझौते को दाखिल करने पर आपत्ति उठाना और मध्यस्थता में न जाने का कारण बताना भारत संघ का काम है। वह कारण न्यायालय की जांच का विषय है। मुख्य अभियंता की भूमिका निष्क्रिय है। भारत संघ कानूनी तौर पर सक्रिय भूमिका निभाता है।

सच्चाई यह है कि डिवीजन बेंच ने न्यायिक अधिनियम और मंत्रिस्तरीय अधिनियम के बीच अंतर नहीं किया। न्यायिक अधिनियम के विपरीत एक मंत्रिस्तरीय कार्य एक कार्य या कर्तव्य है जिसमें प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग शामिल होता है। यदि मुख्य अभियंता नियुक्ति से इंकार करता है तो वह अपना कर्तव्य निभाने से इंकार कर देता है। अगर हम इसे प्रशासनिक शून्यवाद कह सकते हैं तो यह है। वह स्वयं को अपमानित करता है। परंतु वह खंड को नष्ट नहीं कर सकता।

वह उसे सौंपी गई भूमिका में किसी व्यक्तिगत निर्णय या विवेक का प्रयोग नहीं करता है। अपनी शक्ति के प्रयोग के तरीके में उसके पास कोई विवेक नहीं है। यह मानना कि वह इस धारा को नष्ट कर सकता है, उसे ऐसी शक्ति देना है जो उसके पास नहीं है।"

सम्मान के साथ, मैं उस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूँ, जो डिवीजन बेंच ने किशन चंद के मामले (सुप्रा) में लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस पर फुल बेंच ने भरोसा जताया था - प्रफुल्ल कुमार का मामला (सुप्रा), अधिनियम की धारा 20(4) के प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, जहां मध्यस्थता खंड में, किशन चंद के मामले में दी गई शर्त (सुप्रा) और मामला भी हाथ में है।

(5) वास्तव में, जो मूल प्रावधान न्यायालय तक पहुंचने का अधिकार प्रदान करते हैं, वे अधिनियम की धारा 8 और धारा 20 के प्रावधान उस अधिकार को लागू करने के लिए मशीनरी प्रदान करते हैं, जैसा कि मेसर्स में उनके आधिपत्य द्वारा रखा गया है। प्रभात जनरल एजेंसीज आदि बनाम भारत संघ और अन्य (1), जैसा कि उसमें की गई निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट है:

“धारा 20 महज एक मशीनरी प्रावधान है। पार्टियों के मूल अधिकार धारा 8(1)(बी) में पाए जाते हैं। 8(1)(बी) के लागू होने से पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि (1) विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए पार्टियों के बीच एक समझौता है, (2) कि उन्होंने एक मध्यस्थ नियुक्त किया होगा या अपने विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ या अंपायर, (3) उन मध्यस्थ अंपायरों में से किसी एक या अधिक ने उपेक्षा की होगी या कार्य करने से इनकार कर दिया होगा या कार्य करने में असमर्थ हो या उसकी मृत्यु हो गई हो; (4) मध्यस्थता समझौते में यह नहीं दर्शाया जाना चाहिए कि इसका उद्देश्य यह था कि रिक्ति को भरा नहीं जाना चाहिए और (5) पार्टियों या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, ने रिक्ति की आपूर्ति नहीं की थी।

अधिनियम की धारा 8 के तहत, न्यायालय एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है (1) या तो जब

V. K. Construction Works (P) Ltd. o. M/s. Food Corporation
of India and another. (D. S. Tewatia, J.)

समझौते में दोनों पक्षों की सहमति से एक मध्यस्थ का संदर्भ प्रदान किया गया हो और पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति में सहमत नहीं थे, और (2) यदि नियुक्त मध्यस्थ कार्य करने में उपेक्षा या इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या मर जाता है और मध्यस्थता समझौते में यह नहीं दिखाया गया है कि यह इरादा था कि रिक्ति की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए और पार्टियों या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, रिक्ति की आपूर्ति नहीं की। वर्तमान मामले में, पार्टियों को मध्यस्थ की नियुक्ति में सहमत नहीं होना था। वर्तमान मामले में पक्षकार प्रबंध निदेशक या विभाग के प्रमुख द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत हुए थे। वर्तमान मामले में, दूसरी स्थिति भी उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया था और मध्यस्थता खंड में विशेष रूप से परिकल्पना की गई थी कि यदि किसी कारण से मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जाता है या न किया जाता है, तो कार्य करने में विफल रहता है, तो मामला मध्यस्थता के लिए बिल्कुल भी संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए।

(1) A.I.R., 1971 SCC 2298.



(6) वेद प्रकाश मितल (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने यह विचार रखा कि जिस व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए समझौते में अधिकृत किया था, उसे मध्यस्थ नियुक्त न करने के कारण बताने होंगे। बहुत सम्मान के साथ, मध्यस्थता खंड में रेखांकित शर्त का उपरोक्त निर्माण सही नहीं है। किसी भी कारण से 'अभिव्यक्ति' को उस तरीके से नहीं समझा जा सकता जिस तरह से पूर्ण पीठ द्वारा इसका अर्थ लगाया गया है। यह 'किसी कारण' का प्रश्न नहीं है, इसका अर्थ 'कोई कारण नहीं' नहीं हो सकता। मेरी राय में, उक्त शर्त बनाते समय पार्टियों ने जो इरादा और अभिप्राय किया था, वह इस तरह था कि 'यदि किसी कारण से मैं अमुक स्थान पर अमुक समय पर नहीं पहुंचता हूं, तो आपको अब मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।' जिस दल को किसी भी कारण से नियत समय पर दिए गए स्थान पर नहीं पहुंचना चाहिए था, उसे यह कारण बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वह स्थान पर निश्चित समय पर क्यों नहीं पहुंच सका। इस शर्त का उद्देश्य दूसरे पक्ष को नियत समय के बाद प्रतीक्षा करने से मुक्त करना था। यहां भी यही स्थिति है, यदि किसी कारण से मध्यस्थ को प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है या किया जाता है, तो किसी कारण से मध्यस्थ कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए।

(7) उपरोक्त कारणों से, मेरा विचार है कि निचली अदालत ने मध्यस्थता खंड के बारे में सही दृष्टिकोण लिया है और वादी-अपीलकर्ता के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है। इसलिए, मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती और मैं इसे खारिज करता हूं। प्रति आपतियों का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है। हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

R. N. R.

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा